

राज्यपाल की अध्यक्षता में 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया

प्रत्येक जिले में चिन्हित किए गए टीबी मरीजों की संख्या, प्रत्येक मरीज को कितनी बार पोषण पोटली प्रदान की गई, उनकी चिकित्सीय स्थिति में कितना सुधार आया और अब तक कितने मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण

देश से टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना है

जब अधिकारी, कर्मचारी या निःक्षय मित्र स्वयं पोषण पोटली लेकर मरीज के घर जाते हैं, तो न केवल मरीज को मानसिक बल मिलता है, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी आत्मसंतोष और प्रेरणा प्राप्त होती है

टीबी के मरीजों को केवल दवा की ही नहीं, बल्कि प्रेम, सहानुभूति और मानवीयता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है

केवल प्रशासनिक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य के भाव से इस अभियान से जुड़ें अधिकारी

प्रत्येक टीबी रोगी से मिलें, उनकी समस्याएं जानें, उनके परिवार से संवाद करें और उन्हें मानसिक, पोषणीय व चिकित्सकीय सहायता देकर पूर्णतः स्वस्थ होने में सहयोग करें।

—राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अभिनव प्रयोग प्रारंभ हुआ, वह अब पूरे प्रदेश और देश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है

— उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक

लखनऊ : 13 मई, 2025

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन में 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की समीक्षा करते हुए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कितने रोगी स्वस्थ होकर टीबी मुक्त हो चुके हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल नामांकन या गोद लेने तक ही सीमित रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह देखना अधिक आवश्यक है कि गोद लिए गए मरीजों की देखभाल किस स्तर पर की गई,

उन्हें समय पर पोषण पोटलियां दी गईं या नहीं, और उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं निरंतर प्राप्त हुईं या नहीं।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में चिन्हित किए गए टीबी मरीजों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ यह भी रिकॉर्ड रखा जाए कि प्रत्येक मरीज को कितनी बार पोषण पोटली प्रदान की गई है, उनकी चिकित्सकीय स्थिति में कितना सुधार आया है, और अब तक कितने मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि मरीजों का पुनर्परीक्षण कितनी बार कराया गया, इसकी पूरी जानकारी भी नियमित रूप से संकलित की जाए।

राज्यपाल जी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन सभी आंकड़ों को नियमित रूप से अपडेट करें और विश्लेषण कर उन्हें राज्य सरकार को प्रेषित करें ताकि अभियान की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। यह अभियान केवल एक औपचारिकता न बने, बल्कि इसका उद्देश्य प्रत्येक टीबी रोगी को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना और प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना है।

उन्होंने कहा कि देश से टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। यह केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस दूरदर्शी विजन का हिस्सा है, जिसमें भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। राज्यपाल जी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जहां उन्होंने स्वयं आंगनबाड़ियों से इस अभियान की भुरुआत की। इस कार्यक्रम की एक मजबूत रूपरेखा तैयार की और इसके बाद विश्वविद्यालयों को भी इससे जोड़ा, जिससे शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते दिक्कतें आयी, लेकिन महामारी के समाप्त होते ही उन्होंने अभियान को और अधिक सक्रियता से आगे बढ़ाया। अपने जनपद प्रवासों के दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अभियान के प्रारूप को जमीन पर उतारा, और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी रोगियों को चिन्हित कर उन्हें पोषण पोटलियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई।

उन्होंने बताया कि राजभवन से स्वयं इस अभियान की अगुवाई की गई। उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को अभियान से जोड़ा गया। इससे न केवल विश्वविद्यालयों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला, बल्कि समाज को भी सीधा लाभ मिला। राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस मिशन से जुड़ते हुए टीबी रोगियों को गोद लेकर उनके उपचार में योगदान दे रहे हैं। राज्यपाल जी ने यह भी बताया कि अभियान को

प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों और इस कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संस्थाओं को सम्मानित भी किया है।

राज्यपाल जी ने उल्लेख किया कि जी-20 बैठक के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के इस टीबी उन्मूलन अभियान में गहरी रुचि दिखाई और जानना चाहा कि किस प्रकार भारत समाज की भागीदारी से इस दिशा में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी, कर्मचारी या निःक्षय मित्र स्वयं पोषण पोटली लेकर मरीज के घर जाते हैं, तो न केवल मरीज को मानसिक बल मिलता है, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी आत्मसंतोष और प्रेरणा प्राप्त होती है।

राज्यपाल जी ने विशेष रूप से कहा कि टीबी के मरीजों को केवल दवा की ही नहीं, बल्कि प्रेम, सहानुभूति और मानवीयता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने अस्पताल भ्रमण का एक मार्मिक अनुभव साझा करते हुए बताया कि कुछ महिलाएं, जो टीबी से मुक्त हो चुकी थीं, उन्हें उनके परिजन स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से उनको परिवार तक पुनः पहुंचवाया और यह संदेश दिया कि समाज को इस रोग से मुक्त हो चुके व्यक्तियों को अपनाना चाहिए, उन्हें बहिष्कृत नहीं करना चाहिए।

उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे केवल प्रशासनिक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य के भाव से इस अभियान से जुड़ें। प्रत्येक टीबी रोगी से मिलें, उनकी समस्याएं जानें, उनके परिवार से संवाद करें और उन्हें मानसिक, पोषणीय व चिकित्सकीय सहायता देकर पूर्णतः स्वस्थ होने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में करोड़ों रुपये व्यय कर रही है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब समाज भी संवेदनशीलता के साथ अपनी भूमिका निभाए। विश्व में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार और समाज इस स्तर पर एकजुट होकर कार्य कर रहे हों। भारत का समाज अत्यंत संवेदनशील और सहयोगी है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2019 से अब तक कुल 278 टीबी मरीजों को तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अब तक कुल 5,573 टीबी मरीजों को गोद लेकर उनको टीबी से मुक्त करने का काम किया गया है। यह सहभागिता न केवल प्रदेश में टीबी उन्मूलन अभियान को गति प्रदान कर रही है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रसारित कर रही है कि शासन, प्रशासन, शिक्षा जगत एवं समाज सभी मिलकर इस जनकल्याणकारी मिशन में सहभागी बन सकते हैं।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'टीबी मुक्त भारत' विजन की सराहना करते हुए कहा कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अभिनव प्रयोग प्रारंभ हुआ, वह अब पूरे प्रदेश और देश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने राज्यपाल जी को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले राजभवन से इस पहल की शुरुआत की, जहाँ टीवी मरीजों को गोद लेने की व्यवस्था लागू की गई। यह प्रयास न केवल एक उदाहरण बना, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देश भर में फैलाया गया और अंततः इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया।

उपमुख्यमंत्री ने आश्चर्य करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 80 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, और यह लक्ष्य शीघ्र ही पूर्णतः प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश में टीवी उन्मूलन का अभियान मात्र आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जड़ से समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रेरणा के कारण आज यह अभियान प्रशासनिक प्रयासों से आगे बढ़कर सामाजिक भागीदारी का सशक्त उदाहरण बन चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्यपाल जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इस दिशा में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

बैठक में संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्यमंत्री श्री मयंक वर भारण सिंह राजभवन से, मण्डलायुक्त, प्रदेश के 33 जनपदों से जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारीगण वर्चुअली माध्यम से सम्मिलित हुए तथा अपर निदेशक राज्य छय रोग डॉ० भौलेन्द्र भटनागर, निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉ० भुभा मिश्रा राजभवन से जुड़े।

संपर्क सूत्र :

डॉ० संगीता चौधरी,

सूचना अधिकारी, राजभवन

मो०: 9161668080

